

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

20 जुलाई, 2019

“कृषि को बिना सम्मिलित किये 5-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है।”

भारत का 2024 तक 5-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में परिकल्पित होता है। दस्तावेज मुख्य क्षेत्रों के विकास को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रणनीति का पालन करता है। हालांकि, जब तक प्राथमिक क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश सुधार नहीं होते हैं, अन्य क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निरर्थक साबित होंगे।

निवेश सबसे बड़ी कुंजी है

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, पिछले 30 वर्षों में अधिकांश विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश के परिणामस्वरूप कम उत्पादकता और स्थिर उत्पादन हुआ है।

अगर हम यह मान कर चलें कि वार्षिक विकास दर सकारात्मक रहेगी, तो भारत में, 2015-16 के बाद से सकल मूल्य संवर्द्धन की 14.4% की लगातार घटती हिस्सेदारी के साथ, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान 1 ट्रिलियन डॉलर के आस पास होगा।

निवेश एक विकासशील अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने की कुंजी है। हालांकि, पिछले कई दशकों में कमजोर नीति शासन के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि कमजोर रही है। इसलिए, एक सक्षम निवेश पैकेज (सार्वजनिक और निजी दोनों) के साथ क्षेत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

सबसे पहला, निवेश की लहर को कृषि-प्रसंस्करण तथा निर्यात, कृषि-स्टार्टअप और कृषि-पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी सम्मिलित करना चाहिए, जहाँ रोजगार सृजन और क्षमता उपयोग की संभावना बहुत कम है। कृषि-पर्यटन के एक अपेक्षाकृत नए क्षेत्र के साथ मौजूदा पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत करना चाहिए, जहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कृषि क्षेत्र में काम करने वालों और कृषि कार्यो की झलक दिखाई जाती है, जिससे निवेश चक्र को बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।

दूसरा, सार्वजनिक और निजी विस्तार सलाहकार प्रणाली और सहयोग तथा अभिसरण के माध्यम से कृषि-शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए निवेश को संचालित करने की आवश्यकता है। साथ ही यह जैविक, प्राकृतिक और हरित विधियों के माध्यम से संसाधन संरक्षण और सतत् उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (zero budget natural farming) का भी निर्माण करेगा।

तीसरा, यह देखते हुए कि विश्व की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा पशुधन आबादी है, इसलिए अगली पीढ़ी के पशुधन प्रौद्योगिकी को एक मजबूत जोर के साथ नियोजित करके इस अधिशेष का उपयोग करने के लिए निवेश किया जाना चाहिए, जो न केवल उत्पादकता बढ़ाने के लिए हो, बल्कि स्वदेशी जर्मप्लाज्म, रोग निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, अपशिष्ट उपयोग और मूल्य संवर्धन के लिए भी हो। इससे कृषि आय में निरंतर वृद्धि होगी और निर्यात उन्मुख विकास मॉडल के साथ बचत होगी।

चौथा, परती खेत पर और पहाड़ी इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (छोटी पवन चक्की और सौर पंपों का उपयोग करके) में निवेश से ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा सुरक्षा को सक्षम करने के अलावा ऋण-ग्रस्त बिजली वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।

पाँचवां, एक कृषि व्यवसाय संगठन कृषि में निजी निवेश के हस्तांतरण का एक अन्य स्रोत है। इन संगठनों को कमोडिटी एक्सचेंजों

के साथ जोड़ने से कृषि जिंसों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्लेटफार्मों पर अधिक जगह मिलेगी और कुछ नीति/प्रक्रियात्मक संशोधनों के साथ एक आधिक्य सीजन में बाजारों का बोझ कम होगा।

डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका

अंत में, डेटा आधुनिक कृषि का प्रमुख चालक है, जो बदले में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित कृषि, ई-बाजार, मृदा के मानचित्रण जैसे अन्य विकल्पों को शक्ति प्रदान कर सकता है। वर्तमान में, भारत विभिन्न मोर्चों पर कृषि-डेटा को बनाए रखने में मदद करने के लिए गणना, रखरखाव और पहुंच के मुद्दों से जूझ रहा है।

वास्तविक समय (आभासी) के आंकलन के लिए उपलब्ध कृषि स्तर के आंकड़ों को बनाए रखने में मदद करने के लिए एक केंद्रीकृत संस्थागत तंत्र की भी जरूरत है, जबकि सब्सिडी वितरण, वित्त पोषण और उत्पादन अनुमान में अवास्तविक धारणा में खामियों को दूर करने में भी मदद करता है। यह एक व्यावहारिक खाद्य प्रणाली के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने में मदद करेगा।

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि संसाधन संरक्षण व्यवहार परिवर्तन के साथ आता है, जिसे व्यवहार कृषि अनुसंधान सेटों में समर्पित निवेश की आवश्यकता होती है। शायद इससे संसाधनों के संरक्षण, उर्वरक उपयोग, सिंचाई और बिजली की खपत के लिए नीतियों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में वर्णित कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने के लिए खंडित निवेश (सार्वजनिक, निजी और विदेशी) को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

अमीरों से गरीबों की ओर धन प्रवाह

हालांकि, आर्थिक संक्रमण ने सेवाओं और उद्योग का महत्वपूर्ण विकास योगदान देखा है। कृषि, गरीबी, भूख और कुपोषण को कम करने और बेहतर आय वितरण सुनिश्चित करने में सबसे भरोसेमंद क्षेत्र बना हुआ है।

BRIC (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) राष्ट्रों के एक पुराने अनुभव से पता चला है कि गैर-कृषि क्षेत्रों में समान विकास की तुलना में गरीबी को कम करने के लिए कृषि में 1% की वृद्धि कम से कम दो से तीन गुना अधिक प्रभावी है। एग्री जीवीए में प्रतिशत हिस्सेदारी के संदर्भ में कृषि अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश 0.37% है, जो कि विकसित देशों में 3% से 5% की तुलना में काफी कम है।

इसके अलावा, वास्तविक अर्थों में, वर्तमान निवेश आरएंडडी (R-D) में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बना सकता है।

कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों को महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक माना जाता है। हालांकि, कृषि विकास की वर्तमान गति के साथ, भारत को 'पेशेंट कैपिटल' (patient capital) की आवश्यकता है, जिसमें शुरुआती वर्षों में निवेश पर वित्तीय रिटर्न की संभावना नहीं होती है। शासन के लिए एक कानूनी और संस्थागत ढांचे के साथ मजबूत निवेशक-किसान संबंधों को सुविधाजनक बनाने वाला एक समावेशी व्यापार मॉडल बनाया जाना चाहिए। विदेशी कृषि निवेश के विकासात्मक प्रभावों को समायोजित करने के लिए संस्थानों का विस्तार करना आवश्यक है।

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग

क्या है?

- यह एक कृषि अभ्यास है, जिसमें उर्वरकों और कीटनाशकों या अन्य केमिकल तत्वों का प्रयोग किये बिना फसलों को उगाया जाता है। इस तकनीक के तहत खेती करके जो फसल उगाई जाती है, उनका विकास करने के लिए केमिकल की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है और यह खाद खुद से तैयार की जाती है।
- इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में हाईब्रिड बीज, कीटनाशक व रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता है।
- जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र पर आधारित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से एक किसान तीस एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है।
- देसी प्रजाति के गौवंश के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत तथा जामन बीजामृत बनाया जाता है। यह जानना और भी रुचिकर होगा कि खेत में इनका उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ-साथ जैविक गतिविधियों का भी विस्तार होता है।
- गाय के एक ग्राम गोबर में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं, जो किसी भी फसल के लिये आवश्यक 16 तत्वों की पूर्ति करते हैं। इस विधि के अंतर्गत 90 फीसद पानी और खाद की बचत होती है।

उद्देश्य

- कम लागत में उच्च पैदावार, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा तथा बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि का मूल उद्देश्य है।

संबंधित तथ्य

- जीरो बजट खेती के जनक महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों को इस कृषि पद्धति में प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं।
- आंध्र प्रदेश जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य है, जबकि हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है।
- रासायनिक उर्वरक के स्थान पर किसान स्वयं की तैयार की हुई खाद का इस्तेमाल खेती में करते हैं। इस खाद को 'घन जीवामृत' कहा जाता है।

- घन जीवामृत में गाय के गोबर, गौमूत्र, चने के बेसन, मिट्टी, गुड़ व पानी का प्रयोग होता है।
- रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर नीम, गोबर व गौमूत्र का बना हुआ 'नीमास्त' का प्रयोग किया जाता है।
- बाजार के हाईब्रिड बीजों के स्थान पर देशी बीजों का प्रयोग फसल उत्पादन के लिए होता है।
- खेतों की सिंचाई, गुड़ाई व जुताई का कार्य घरेलू पशुओं द्वारा किया जाता है।
- जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को प्रारंभ में सितंबर, 2015 में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था।
- जीरो बजट कृषि पद्धति रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित कर बेहतर कृषि पद्धति को संचालित करती है।
- इस कृषि पद्धति में किसान की लागत अत्यंत कम होती है, क्योंकि जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे- गाय का गोबर, पेड़-पौधे व वनस्पतियां, मल-मूत्र, केंचुआ निःशुल्क व बड़ी मात्रा में गाँवों में उपलब्ध होते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि और खाद्य प्रबंधन

- सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) 2014-15 में देश के कृषि क्षेत्र ने 0.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि से उबरकर 2016-17 में 6.3 प्रतिशत की विकास दर हासिल की, लेकिन 2018-19 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई।
- सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2017-18 में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 15.2 प्रतिशत घटा। 2016-17 में यह 15.6 प्रतिशत रहा था।
- कृषि में 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का जीसीएफ जीवीए के प्रतिशत के रूप में 2.7 प्रतिशत बढ़ा। 2013-14 में यह 2.1 प्रतिशत के स्तर पर था।
- कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 2005-06 की अवधि के 11.7 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई।
- छोटे और सीमांत किसानों में ऐसी महिलाओं की संख्या 28 प्रतिशत रही। 89 प्रतिशत भू-जल का इस्तेमाल सिंचाई कार्य के लिए किया गया है।
- दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र पर आधारित है।
 2. इसका उद्देश्य कम लागत में उच्च पैदावार, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा तथा बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति है।
 3. इसे अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य आन्ध्र प्रदेश है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- (a) 1 और 3
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. In reference to the zero budget Natural farming consider the following statements-
1. It is based on the dung and urine of indigenous cow.
 2. Its objectives is high yeild with low cost, protection from climate change and attainment of good health.
 3. Andhra Pradesh is the first state of India to adopt it.
- Which of the above statement is/are correct?
- (a) 1 and 3 (b) Only 2
(c) 1 and 2 (d) All of the above

Expected Questions (Mains Exams)

- प्रश्न: एक सक्षम निवेश मॉडल (सार्वजनिक निजी दोनों) किस प्रकार कृषि क्षेत्र में निवेश संबंधी समस्या को दूर कर भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना साकार कर सकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
- Q. How can a capable investment both public and private fulfill the dream of 5 million dollar economy of India by tackling the investment related problems of agriculture discuss. (250 Words)

नोट : 19 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

Committee